(b) if so, what amount is likely to be spent on Bhiwani Textile Mills;

(c) whether Government have any proposal to open new Textile Mills in Haryana; and

(d) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) There is no mill of NTC in Haryana.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

वर्ष 1992 के दौरान कपड़े का कम उत्पादन

1016. **श्री रामजेठमलानी :**

श्री विष्णुकांत शास्त्री : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1992 के दौरान संगठित कपड़ा मिलों में उत्पादित कपड़े की मात्रा वर्ष 1991 के उत्पादन की तुलना में कम थी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 तथा 1992 में कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या सरकार ने इन कपड़ा मिलों द्वारा 1992 में उत्पादित कपड़े के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया था ;

(घ) यदि हां, तो वह लक्ष्य कितना था ;

(ङ) उन मिलों में कम उत्पादन होने के कारण क्या हैं; और

(च) इन मिलों की उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कपड़े का उत्पादन 2376 मि. वर्ग मीटर था जिसकी तुलना में वर्ष 1992-93 में 2255 मि. वर्ग मीटर कपड़े के उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1996-97 के लिए संगठित वस्त्र मिल उद्योग में कपड़े के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । मिल क्षेत्र के लिए 4150 मि. वर्ग मीटर उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ङ) (i) विद्युत करघा क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा, (ii) बुनाई क्षमता को अलग करना ।

(च) (31-10-1992 की स्थिति अनुसार) 1133 मिलें हैं जिनमें 27.92 मि. तकुए, 114 हजार रोटर तथा 169 हजार करघे हैं ।

1096 RSS/94—19

विद्युत चालित करघा तथा हथकरघा क्षेत्र के लिए सूत की जरूरत

1017 **श्री राम जेठमलानी:**

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच कि हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों को कच्चा माल प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती हैं तथा वे अकसर इस मामले में अपनी शिकायतें दर्ज करवाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इनके लिए पर्याप्त मात्रा में सूत उपलब्ध करवाने के लिए कई कदम उठाए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने क्रमश: हथकरघा तथा विद्युत करघा क्षेत्र के उद्योगों की सूत की वार्षिक आवश्यकता का कोई आंकलन किया है ;

(घ) यदि हां, तो हथकरघा तथा विद्युतकरघा क्षेत्र की अलग-अलग वार्षिक जरूरत कितनी-कितनी है;

(ङ) इन दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे बुनकरों को सूत उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने कौन से इंतजाम किए हैं ; और

(च) क्या यह भी सच है कि इन दोनों क्षेत्रों की अधिकतर इकाईयां दुर-दराज के क्षेत्रों में फैली हुई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) हथकरघा बुनकरों को कच्चे माल की उपलब्धता में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन शिकायत सूत के मूल्यों में वृद्धि/इसके मल्यों में उतार-चढ़ाव से संबंधित है।

(ख) जी हां।

(ग) जी, हां।

(घ) हथकरघा क्षेत्र में सूत की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान 400 मिलियन किलोग्राम लगाया गया है। पावरलूम और होजरी क्षेत्र में सूत की वार्षिक आवश्यकता लगभग 1000 मिलियन किलोग्राम है।

(ङ) सरकार ने हथकरघा व पावरलूम क्षेत्रों में सूत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे :—

(1) नई औद्योगिक नीति का सरलीकरण जो कताई क्षेत्र में वर्तमान इकाईयों का विस्तार क्षमता और नई इकाईयों में क्षमता सृजन करने की अनुमति देता है बशर्ते स्थानीय बाधायें न हों।

(2) बुनकर सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों की स्थापना के लिए सहायता; और

(3) हैंक यार्न दायित्व आदेश।

(च) हथकरघा क्षेत्र में तो ऐसा है ही लेकिन पावरलूम अधिकांश रूप से देश के विशेष क्षेत्रों में केन्द्रित हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तहत रुग्ण कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

1018. डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

श्री राम जेठमलानी :— क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तहत चलने वाली कपड़ा मिलों को बन्द करने का फैसला किया ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ग) इन कपड़ा मिलों को बन्द किए जाने के कारण बेरोजगार होने वाले कामगारों की संभावित संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार इन कामगारों के पुनर्वास हेतु इन्हें कहीं और काम देने की किसी योजना पर सोच-विचार कर रही है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मिलों के बन्द किए जाने के फल-स्वरूप राष्ट्रीय वस्त्र निगम के वार्षिक घाटे में कितनी कमी होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है। चुनिन्दा आधुनीकीकरण, वित्तीय पुनर्निर्माण तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना द्वारा फालतू श्रमिक बल का सुव्यवस्थीकरण करना इस नीति के प्रमुख अंग हैं। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की पेशकश उन दीर्घकालिक रुग्ण मिलों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कामगारों को भी की जाएगी जिनके अर्थक्षम होने की कोई संभावना नहीं है तथा जिन्हें बन्द करना अथवा निकटस्थ एककों के साथ मिलाना पड़ सकता है ताकि अर्थक्षमता सुनिश्चित की जा सके। तथापि, अलग-अलग मिलों को बनाए रखने अथवा बन्द करने के प्रश्न को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तथा अन्य सम्बद्ध कारकों का उनकी अर्थक्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद ही उठाया जाएगा। ऐसी परिकल्पना की गई है कि एन टी सी के लगभग 75,000 कामगार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठायेंगे। सर्वांगीण सुधार नीति में भी सुव्यवस्थित किए गए कामगारों को पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः नियुक्ति करने के लिए 50 करोड़ रु. की राशि से पुनर्वासन निधि का सृजन किया गया है। ऐसी आशा है कि इस सर्वांगीण सुधार नीति के सफल कार्यान्वयन से लगभग 3 वर्षों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम का कायाकल्प हो जाएगा।